SUGAR FACTORIES IN ANDHRA PRADESH

4957. SHRI M. N. REDDY: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the 19 sugar factories of Andhra Pradesh have offered only Rs. 90 per tonne of sugarcane to the cane-growers during this season due to which the cane supplies to the factories have been stopped by the growers thus creating a serious crisis in the sugar industry; and

(b) if so, the measures being contemplated by Government to ensure the adequate production of sugar in Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) and (b). According to information received from sugar factories, which have commenced production, the price of sugarcane being paid is Rs. 8 to 10 per quintal. No information has been received about stoppage of supplies of sugarcane to factories in Andhra Pradesh. The State Government is persuading factories to increase the price of cane.

सहकारी समितियों का एकीकरण

4958. श्री क० मि० मधुकर: क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों को समितियों के एकीकरण या उनके द्विभाजन करने का अधिकार नहीं है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ राज्यों में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों ने पुनर्गठन के नाम पर कुछ सहकारी समितियों का एकीकरण किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) जी नहीं। कुछ राज्य सरकारों के सहकारी अधिनियमों के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को आवश्यक अधिकार हैं।

(ख) व (ग). जिन राज्यों में रजिस्ट्रार को समितियों के एकीकरण या उनके द्विभाजन करने के सांविधिक अधिकार हैं, वहां उचित परिस्थितियों में ऐसे अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। तथापि, यह मामला मुख्यत: राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में सहकारी अधिनियम राज्य विधानमण्डलों द्वारा पारित किए जाते हैं।

सहकारी समितियों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना

4959. श्री क० मि० मधुकर: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने 1 नवम्बर, 1967 को राष्ट्रीय सहकार सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह आश्वासन दिया था कि सहकारी समितियों को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो यह अध्ययन दल कब नियुक्त किया जाएगा, इसके निर्देश पद क्या होंगे और यह कब तक अपना कार्य आरम्भ करेगा?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) तथा (ख). 1 नवम्बर, 1967 को कोई